



डटिंशन सेंटर

संदर्भ:

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 पारित होने के बाद देश में डटिंशन सेंटर (Detention Centre) को लेकर बहस तेज हो गई है। डटिंशन सेंटर को लेकर सरकार और विधिक्ष के दावों में अंतर है। ऐसी स्थिति में डटिंशन सेंटर व उसकी कार्यप्रणाली को समझना हमारे लिये बेहद आवश्यक हो जाता है।

इसके साथ ही हमें इस तथ्य पर भी विचार करना होगा कि प्रगतिशीलता और मानवाधिकारों की इस सदी में डटिंशन सेंटर जैसी अवधारणा क्या है? क्या अवैध आप्रवासन जैसी समस्या से निपटने के लिये अब यही अंतिम विकल्प शेष रह गया है या कहीं ऐसा तो नहीं कि अवैध आप्रवासन जैसी समस्या के समाधान की इस प्रक्रिया को संदेह के रूप में देखा जा रहा है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे।

क्या है डटिंशन सेंटर?

- डटिंशन सेंटर उस स्थान को कहते हैं जहाँ विदेशी तरीके (वैध दस्तावेजों का अभाव) से देश में प्रवेश करने वाले विदेशी लोगों को रखा जाता है।
- यद्यपि डटिंशन सेंटर एक नवीन अवधारणा है परंतु पुरातन काल में भी इससे मलिती-जुलती व्यवस्थाओं के साक्षय प्राप्त होते हैं, आधुनिक काल में जर्मनी, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में डटिंशन सेंटर के स्पष्ट प्रमाण मलिते हैं।
- विशेष का पहला इमिशन डटिंशन सेंटर वर्ष 1892 में अमेरिका के न्यू जर्सी में स्थापित किया गया था।
- वर्ष 1970 में यूरोप का पहला डटिंशन सेंटर इंगलैण्ड में प्रारंभ किया गया।
- वर्ष 1982 में अफ्रीका महाद्वीप का पहला डटिंशन सेंटर दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया।
- वर्ष 2012 में इजराइल ने होलोट डटिंशन सेंटर प्रारंभ किया।
- भारत में वर्ष 2008 तक डटिंशन सेंटर जैसी व्यवस्था नहीं थी परंतु जुलाई 2008 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक निरिण्य देते हुए कहा कि "अक्सर लोग विदेशी घोषित होने के बाद गायब हो जाते हैं, इसलिये उन्हें पकड़कर रखने के लिये राज्य सरकार डटिंशन सेंटर की व्यवस्था करे ताकि उन्हें यहाँ से निवासित किया जा सके"।
- तदुपरांत असम सरकार ने केंद्र सरकार से परामर्श कर 17 जून 2009 को राज्य में डटिंशन सेंटर स्थापित करने की अधिसूचना जारी की।
- इस तरह देश का पहला अस्थायी डटिंशन सेंटर गवालपाड़ा जेल में स्थापित किया गया।

निवासन के वैधानिक पक्ष:

- विदेशी अधिनियम (The Foreigners Act), 1946 की धारा 3(2)(c) के अनुसार देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को निवासित करने की शक्ति केंद्र में नहित है।
- संविधान का अनुच्छेद 258 राज्य सरकारों को भी इस तरह के कदम उठाने में सक्षम बनाता है।
- संविधान के अनुच्छेद 258(1) में उपबंधित है कि "संविधान में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, किसी राज्य की सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य, जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा"।
- जनवरी 2019 में गृह मंत्रालय द्वारा मॉडल डटिंशन सेंटर पर एक विस्तृत मैनुअल जारी किया गया, जिसका उद्देश्य जेल और डटिंशन सेंटर के मध्य अंतर स्पष्ट करना था।

Centre	State	Status
Goalpara district jail	Assam	Operational
Kokrajhar	Assam	Operational
Silchar	Assam	Operational
Dibrugarh	Assam	Operational
Jorhat	Assam	Operational
Tezpur	Assam	Operational
Lampur	Delhi	Operational
Mapusa	Goa	Operational
Alwar Central jail	Rajasthan	Operational
Amritsar Central jail	Punjab	Operational
Goalpara	Assam	Under construction
Tarn Taran	Punjab	Under construction
Bengaluru	Karnataka	Under construction
Nerul	Maharashtra	Location identified*
New Town	West Bengal	Location identified^
Bongaon	West Bengal	Location identified^

देश में डटिंशन सेंटर्स की स्थानीयता://

- दलिली के वाह्य क्षेत्र लामपुर में एक डटिंशन सेंटर स्थापित किया गया है, जिसका परचिलन नयिंत्रणक्षेत्रीय विदेशी पंजीकरण कार्यालय (**Foreigners Regional Registration Office**) और रखरखाव दलिली सरकार द्वारा किया जाता है।
- गोवा के मापुसा में एक डटिंशन सेंटर की स्थापना की गई है तो वही राजस्थान के अलवर में स्थानीय कारागार में एक डटिंशन सेंटर स्थापित किया गया है।
- मई 2020 तक पंजाब के तरनतारन में स्थानीय डटिंशन सेंटर के परचिलन की संभावना है जबकि कर्नाटक के बंगलूरु में स्थानीय डटिंशन सेंटर 1 जनवरी 2020 से परचिलन में है।
- वही असम में क्रमसः ग्वालपाड़ा केंद्रीय कारागार, कोकराझार, सलिचर, डबिरूगढ़, जोरहाट, तेजपुर में डटिंशन सेंटर स्थापित किया गए हैं।

क्या डटिंशन सेंटर आवश्यक हैं ?

- जब कोई व्यक्ति किसी अन्य देश में वधिविरुद्ध तरीके से नवास करता है तो उस पर अभियोग चलाया जाता है और उसके द्वारा निर्धारित सजा पूरी करने के बाद उस अन्य देश के पास प्रथम वकिलप के रूप में उस व्यक्ति को उसके मूल देश में निवासित करने का अधिकार होता है।
- यदि अवैध प्रवासी व्यक्ति को उसके मूल देश द्वारा अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया जाता है तब ऐसी स्थानीय में उसके समक्षाज्यहीनता (**Stateless**) का संकट उत्पन्न हो जाता है। इस विषय पर स्थिति में मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर उस व्यक्ति की पहचान को सुनिश्चित करने के लिये उसे डटिंशन सेंटर में रखा जाता है।
- डटिंशन सेंटर में रहे व्यक्तियों को भारत के “नागरिकों” की भाँति सभी मूल अधिकार नहीं प्राप्त होते परंतु भारत के संविधान में “व्यक्तियों” को प्राप्त मूल अधिकार उन्हें भी प्राप्त होते हैं।

निषिकरण:

वस्तुतः भारत में डटिंशन सेंटर की स्थापना गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए “विदेशी व्यक्तियों” की पहचान और उन्हें सुरक्षित रखने हेतु की गई। इसका भारत के किसी भी नागरिक से कोई संबंध नहीं है। सरकार को अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिये तथा नागरिक समाज को इस संबंध में जागरूकता फैलाने का कार्य करना चाहिये।

स्रोत: द हॉटि